whether the Government is considering special programme to impart modern technology to promote and develop food processing units in rural areas especially in the North East. I would also like to know whether the Government envisages taking steps to develop food processing units at the cottage level.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, in the Horticulture Mission and the Mini Mission, North East is a special focus area. Upgradation of technology is included in it. As I said, in this Summit in the North East, the Chief Ministers and all concerned are coming. We are going to discuss these issues in detail. If any hon. Member wants to join that Summit, he is welcome.

*284. [*The questioner (Shri N.K. Premachandran) was absent. For answer vide page* 28.]

Increasing forest cover

*285. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have made any comprehensive strategic plan for increasing the forest cover by maintaining greenery in the country for the next twenty years;

(b) if so, the details thereof;

(c) what steps have been taken or proposed to be taken for increasing forest cover in the country;

(d) the estimated amount to be spent on this plan and whether Government have chalked out any plan for the increasing participation of local people in these plans; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The National Forestry Action Programme (NFAP) of India 1999 is a 20 year persective plan for the forestry sector of the

country. The programe document envisaged expansion of forest and tree cover by 21.80 million hectares besides regeneration of 26.43 million hectares of existing forest area with a proposed total investment of Rs. 133902.78 crores in 20 years.

(c) Following steps have been taken to increase the forest and tree cover in the country:—

(i) Ministry of Environment and Forests is implementing National Afforestation Programme (NAP) Scheme for regeneration of degraded forests and adjoining forestlands during the Tenth Five Year Plan. The Scheme is being implemented through two-tier decentralized mechanism of Forest Development Agency (FDA) at forest division level and Joint Forest Management Committees (JFMCs) at village level. As on 06.02.2006, 680 FDA projects have been approved in all 28 States at a total cost of Rs. 1489.42 crores to cover project area of 9.04 lakh hectares through 22,878 JFMCs.

(ii) Consultation with State Governments and Union Territory (UT) administration, including conferences of Forest Ministers of States and Union Territories on 5-6 August, 2004 and 15 February, 2006, have been held to sensitize State/UT authorities about the increased tree planting targets.

(iii) State Government and Union Territory Administrations have been requested to constitute Chief Secretary-level Committee of all land owning and other concerned Departments to involve them in tree planting activities.

(iv) Guidelines for rationalization of felling and transit regulations for tree species grown on non-forest private land have been issued by the Ministry of Environment and Forests to the State Governments and Union Territory Administrations to encourage private tree plantation.

(v) State Government and Union Territory Administrations have been requested to formulate and implement a comprehensive Media Plan to create mass awareness about tree planting.

(vi) Multi-Stakeholder Partnership (MSP), involving State Forest Department, the local village community and the private sector, has been mooted for forestation of degraded lands.

(d) and (e) The NFAP 1999 envisaged a total investment. of Rs. 133902.78 crore in 20 years. People's participation is considered as an important element of forestry sector in the country. The Ministry has issued guidelines dated. 1.6.1990 for involving village communities and voluntary agencies for regeneration of degraded forest land within conceptual framework of Joint Forest Management (JFM). The Ministry is implementing National Afforestation Programme (NAP) during the Tenth Five Year Plan to institutionalize and expand JFM. As per information received from States, 99,868 JFMCs are functioning in all 28 States covering 21.4 million hectares of forest area. An allocation of Rs.1205 crores has been provided for NAP during the Tenth Five Year Plan.

श्री संजय राउत: सर, मैंने सरकार का उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ा है। हरित क्षेत्रों एवं जंगलों के वृद्धिकरण एवं रक्षा के लिए सरकार ने भारी भरकम कार्यक्रम बनाए हैं और आगामी 20 वर्ष के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया है। लेकिन इसके बावजूद आज देश के अन्दर जंगल नष्ट होते चले जा रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं और वन क्षेत्र की कटाई हो रही है।

सर, मुझे लगता है कि जंगलों के अन्दर जो फॉरेस्ट माफिया गैंग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जंगलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जंगलों में ये जो माफिया गिरोह अपना काम करते हैं, इसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है? सरकार के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ क्या उनकी कोई मिली-भगत सामने आई है? यह राज्य एवं केन्द्र, दोनों का प्रश्न है। इन माफिया गैंग्स की वजह से जंगल ज्यादा नष्ट हो रहे हैं, अत: मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके इस वनीकरण कार्यक्रम से कुछ होने वाला नहीं है। जो फॉरेस्ट गैंग्स हैं, हर राज्य में जो छोटे-छोटे वीरप्पन बैठे हुए हैं, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक वन क्षेत्र के डिप्लीशन की बात है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। 2003 में जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार देश का वन क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ा है और यह 23.68 प्रतिशत रहा है। माननीय सदस्य ने जहां तक वन क्षेत्रों की कटाई की बात की है, इस चीज़ से मैं सहमत हूं कि जंगलों के अन्दर कटाई हुई है और राज्य सरकारों ने इसके ऊपर ऐक्शन भी लिया है। जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशन्स के इम्प्लिमेंटेशन का सवाल है, यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वे इन फॉरेस्ट गैंग्स के खिलाफ ऐक्शन लें। मेरे पास जो फिगर्स हैं, उनके अनुसार 2003-04 तक फॉरेस्ट ऐक्ट के तहत लगभग छ: लाख केसिज़ बने हैं और काफी मात्रा में टिम्बर भी पकड़ा गया है।

श्री संजय राउत: सर, मेरा एक प्रश्न महाराष्ट्र के बारे में भी है। आज महाराष्ट्र के वन क्षेत्र का भी भारी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में पहले फॉरेस्ट कवर 30% था, लेकिन अब वह नीचे

आ रहा है। आपके पास महाराष्ट्र के बारे में क्या जानकारी है? वहां का वन क्षेत्र क्यों नष्ट हो रहा है और उसके बारे में केन्द्र सरकार का क्या रवैया है?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, हमारे पास वन स्थिति की 2003 की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में ओपन वन क्षेत्र बढ़ा है, कम नहीं हुआ है....(व्यवधान)।

श्री संजय राउत: नहीं, मेरे पास जानकारी है कि यह कम हुआ है और 30% से भी नीचे आ गया है। आपकी जानकारी क्या है?

श्री नमो नारायण मीणा: यह जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन मेरे पास अभी जो रिपोर्ट उपलब्ध है, इसमें हमारे हिसाब से ...(व्यवधान)।

श्री संजय राउत: मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों में 10 फॉरेस्ट गैंग्स पकड़े गए है।

श्री सभापति: रिपोर्ट नई हो या पुरानी हो, लेकिन ये रिपोर्ट में से ही बोल रहे हैं।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, महाराष्ट्र के संबंध में जो रिपोर्ट हमारे पास छपी हुई उपलब्ध है, उसमें इंटरप्रिटेशनल चैंजिज़ की वजह से कुछ गलतियां हुई हैं जिस विधि के अनुसार हम फॉरेस्ट क्षेत्र का आकलन करते हैं, उसमें 2001 की रिपोर्ट में कॉटन, शुगरकेन ...(व्यवधान)...

श्री संजय राउत: अब 2006 चल रहा है, आप 2001 की बात छोड़िए।

श्री नमो नारायण मीणा: इसमें बहुत ज्यादा डिप्लीशन नहीं हुआ है, थोड़ा-बहुत ही हुआ है, वह जस्टिफाइड भी है ...(व्यवधान)।

श्री संजय राउत: मैं 2005-06 की बात कर रहा हूं, आप मुझे 2001 की बात मत बताइए।

श्री नमो नारायण मीणा: अगर कोई गैंग्स वगैरह पकड़े गए हैं तो संबंधित कानून के तहत स्टेट गवर्नमेंट को उनके खिलाफ ऐक्शन ले लेना चाहिए।

श्री संजय राउत: नहीं सर, यह तो गलत बात है, आप 2001 की बात कर रहे हैं।

MS. PRAMILA BOHIDAR: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the creation of green belt and forest cover is commensurate with the money spent on them. I ask this because it is alleged that a lot of money has been wasted on this effort.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, फारेस्ट इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल स्कीम्ज हैं, फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। यह बात जरूर है कि फॉरेस्ट के ऊपर एग्रीकल्चर प्रैशर है, माइनिंग का प्रैशर है, पौपुलेशन का प्रैशर है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले सालों में हमारे देश का

फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ रहा है और टेंथ प्लान के एंड में 25 परसेंट जो हमारा कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको हम अचीव कर लेंगे।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, deforestation is one of the great disasters that afflicts the country, causing desertification, species' destruction, erosion which has just been mentioned by the Minister of Agriculture, and all-round disaster.

Sir, the Minister's assertion that the forest cover in this country has grown is not, unfortunately, borne out, or, not accepted by environmentalists. They, in fact, are very worried on the basis of satellite photographs that the forest cover is shrinking. May I ask the Minister, first of all, whether his assertion that the forest cover is growing is based on the latest satellite-imaging technology and, secondly, is he closely monitoring the progress of the schemes—and the schemes that he has mentioned are extremely good—to ensure that we are able to reach our target of 25 per cent?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, यह बात सही है जैसा मैंने पहले बताया कि फारेस्ट कवर के ऊपर एग्रीकल्चर का प्रैशर है, माइनिंग का प्रैशर है, पोपुलेशन का प्रैशर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी रिपोर्ट छपी है उसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, घटा नहीं है। जो भी सारी रिपोर्ट छपी है, वह सेटलाइट इमेजरी प्रोसैस के आधार पर छपी है। ....(व्यवधान)

श्री शरद यादव: यदि यह रिपोर्ट ही पढ़नी है तो वह रिपोर्ट हमारे पास ही है। मंत्री जी यहां क्यों पढ़ रहे हैं। पूरा देश जानता है कि फॉरेस्ट घट रहा है। ये कह रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट में बढ़ गया है। ...(व्यवधान)

Disbursement of subsidies to BPL, poor and marginal farmers

*286. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that main recipients of subsidy are surplus producting farmers of five States from where procurement is done at the prices set by Government;

(b) if so, whether the disbursal of subsidy can be improved with a view to ensuring the BPL consumers/small and marginal farmers get the intended benefit of subsidies; if not, the reasons therefor; and